कार्यालय

मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश

लोक भवन, लखनऊ

संख्या .... दिनांक ....

<u>प्रमुख सचिव, आवास</u>

कृपया दैनिक हिन्दुस्तान, लखनऊ समाचार पत्र दिनांक 18 मार्च, 2021 में ''पुरातत्व विभाग रूकवाता, एलडीए बनवाता रहा दाउद की अवैध बिल्डिंग'' के शीर्षक से प्रकाशित समाचार की संलग्न कतरन का अवलोकन करें।

कृपया जॉचोपरान्त तत्कालीन अधिकारियों का दोष निर्धारित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही कर आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

<u>संलग्नकः यथोक्त</u>

18-03-2021

(संजय प्रसाद)
प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री
उ० प्र० शासन।

प्राप्त सी० एम० -2
19 MAR 2021
आख्या

CRCD000561850972

Maurya-M

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ 18 MAR 2021

समाचार पत्र का नाम दै0 हिन्दुस्तान, लखनऊ दिनांक

पुरातत्व विभाग रुकवाता, एलडीए बनवाता रहा दाउद की अवैध बिल्डिंग

मिलीभगत

04 मंजिल का नक्शा पास हुआ था पूर्व सांसद दाउद अहमद की बिल्डिंग का

05 वीं मंजिल बिना नक्शा पास कराए बनायी, गिराने की कार्रवाई शुरू

लखनऊ | प्रमुख संवाददाता

पूर्व सांसद दाउद अहमद की अवैध बिल्डिंग बनवाने में एलडीए के इंजीनियरों का नाम सामने आया है। पुरातत्व विभाग व लखनऊ के तत्कालीन. कमिश्नर एलडीए को लगातार इस बिल्डिंग का निर्माण रुकवाने के लिए पत्र लिखते रहे लेकिन प्राधिकरण के इंजीनियरों व अधिकारियों ने बिल्डिंग का निर्माण नहीं रुकवाया। अब पांच मंजिल बिल्डिंग बन जाने के बाद अधिकारी एक मंजिल को अवैध बताकर उसे तोड़ने की औपचारिकता निभा रहे हैं।

एलडीए को आधा दर्जन पत्र लिखे: दाउद अहमद ने जो बिल्डिंग बनवाई है एलडीए ने उसका चार मंजिला नक्शा पास किया है। पुरातत्व विभाग ने इस बिल्डिंग के लिए एलडीए को आधा दर्जन पत्र लिखे हैं। वह एलडीए के अधिकारियों को 2019 से ही लगातार पत्र लिखता रहा है। बिल्डिंग संरक्षित स्मारक रेजीडेंसी के दायरे में आ रही थी। लिहाजा इसका निर्माण नहीं हो सकता था। इसके बावजूद अधिकारियों ने निर्माण नहीं रुकवाया और अब पूरी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई।

पूर्व सांसद की रेजीडेंसी के पास बनी बिल्डिंग में बुधवार को अवैध निर्माण तोड़ा गया।

कमिश्नर ने भी एलडीए को लिखा था पत्र

संरक्षित इमारत के पास बन रही बिल्डिंग का निर्माण रुकवाने के लिए अगस्त 2019 में तत्कालीन कमिश्नर ने भी एलडीए उपाध्यक्ष व सचिव को पत्र लिखा था। बाद में यह पत्र संयुक्त सचिव ऋतु सुहास के पास भी पहुंचा था। हिन्दुस्तान ने 20 अगस्त 2019 के अंक में पुरातत्व विभाग व कमिश्नर के पत्र के हवाले से इस बिल्डिंग के निर्माण की खबर प्रकाशित की थी। तत्कालीन संयुक्त सचिव व विहित प्राधिकारी का काम देख रही ऋतु सुहास ने भी इसके खिलाफ कार्रवाई की बात की थी।